

प्रेषक,

मनीषा पंवार,

सचिव,

उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. निदेशक,

समाज कल्याण, उत्तराखण्ड,  
हल्द्वानी, जनपद-नैनीताल।

2. निदेशक,

जनजाति कल्याण, उत्तराखण्ड,  
देहरादून।

समाज कल्याण अनुभाग-01.

देहरादून, 03 सितम्बर 2008.

विषय : प्रदेशा में गरीबी की रेखा से नीचे निवास कर रहे अनुसूचित जाति के परिवारों की बालिकाओं एवं गरीबी की रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले समस्त परिवारों की बालिकाओं द्वारा इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण करने पर बालिका शिक्षा को प्रोत्साहन देने हेतु 'कन्याधन' योजना के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या-1625/XVII(1)-1/2006-19(08)/2006, दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के प्रस्तर-5 को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है-

"5. योजना के अन्तर्गत समिति द्वारा चयनित प्रति छात्रा को रुपये 25,000/- की धनराशि 'कन्याधन' के रूप में स्वीकृत की जाएगी। धनराशि का भुगतान दो प्रकार से हो सकेगा। छात्रा को निम्न दो विकल्पों में से किसी एक का चयन करना होगा-

(1) छात्रा के नाम से राष्ट्रीय बचतपत्र, अथवा

(2) धनराशि भारतीय स्टेट बैंक की शाखा में छात्रा के नाम से तीन से पांच वर्ष की सावधि जमा (Fixed Deposit) के रूप में रखी जाए तथा जिस पर रुपये 206/- मासिक का ब्याज दिया जाएगा। सावधि जमा की समय सीमा समाप्त होने पर मूलधन छात्रा को देय होगा। सावधि जमा प्रतिभूति के आधार पर छात्रा बैंक से ऋण भी प्राप्त कर सकती है।"

2. शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2006 के प्रस्तर-6 को निम्न प्रकार संशोधित किया जाता है:-

"6. ग्रामीण क्षेत्र में बी0पी0एल0 क्रमांक अंकित अथवा वार्षिक आय रुपये 15,976/-के आय प्रमाण पत्र तथा शहरी क्षेत्र में रुपये 21,206/-की वार्षिक आय प्रमाण पत्र जो राजस्व विभाग के सक्षम अधिकारी जिसका स्तर तहसीलदार से कम न हो, के आधार पर मान्य होगा, संलग्न किया जायेगा।

3. इसी प्रकार सन्दर्भित शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2008 के परिशिष्ट- 'क' (कन्याधन योजना-आवदेन का प्रारूप) के क्रमांक-8 के पश्चात् क्रमांक-9 निम्नानुसार स्थापित किया जाए-

"9. धनराशि के भुगतान हेतु छात्रा द्वारा चयनित विकल्प :

- (1) राष्ट्रीय बचतपत्र, अथवा
- (2) भारतीय स्टेट बैंक में सावधि जमा।"

4. उक्त आदेश शैक्षिक सत्र 2007-08 में सम्पन्न हुए इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण बालिकाओं पर भी लागू माना जायेगा।

5. उपरोक्त शासनादेश दिनांक 27 दिसम्बर 2006 को इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

भवदीय,

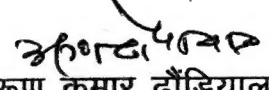
(मनीषा पंवार)  
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या 919 (1)/XVII-1/2008-19(08)/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव—महामहिम श्री राज्यपाल महोदय, उत्तराखण्ड।
2. निजी सचिव—माननीय मुख्यमंत्री/समस्त माननीय मंत्रीगण, उत्तराखण्ड।
3. निजी सचिव—मुख्य सचिव/अपर मुख्य सचिव महोदय, उत्तराखण्ड शासन।
4. समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
6. सचिव, शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक), उत्तराखण्ड शासन।
7. समस्त मण्डलायुक्त/जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
8. निदेशक, कोषागार एवं वित्त सेवाएं, उत्तराखण्ड, देहरादून।
9. निदेशक, शिक्षा (विद्यालयी एवं माध्यमिक), उत्तराखण्ड।
10. समस्त मुख्य विकास अधिकारी/जिला समाज कल्याण अधिकारी/जिला कार्यक्रम अधिकारी/जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
11. समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
12. उप महाप्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, सेल्स अनुभाग, उत्तरांचल आंचलिक कार्यालय, 1, न्यू कैण्ट रोड, देहरादून को उनके पत्रांक-2585, दिनांक 21 अगस्त 2008 के क्रम में इस आशय से प्रेषित कि कृपया समस्त शाखा प्रबन्धकों को यथोचित निर्देश जारी करने का कष्ट करें।
13. समस्त शाखा प्रबन्धक, भारतीय स्टेट बैंक, उत्तराखण्ड।
14. वित्त (व्यय नियन्त्रण) अनुभाग-03, उत्तराखण्ड शासन।
15. राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
16. आदेश पंजिका।

आज्ञा से,

  
(अरुण कुमार ढौंडियाल)  
अपर सचिव।